

संपादकीय मोटापे की दवाएं

सं सार में मोटापा एक बड़े रोग की तरह फैल रहा है और ऐसे में मोटापे की दवा खोजने में लगे वैज्ञानिकों का समान सुखद व खामोशिक है। वैसे तो मोटापे की दवा खोजने के अधिकार में अनेक वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, पर उनमें से तीन वैज्ञानिकों को इस वर्ष के प्रतिष्ठित लास्कर पुरस्कार के लिए नुना गया है। उससे कामयाब मोटापा-विरोधी दवाओं को विकसित करने में शामिल इन तीन वैज्ञानिकों के बारे में माना जा रहा है कि इन्हें विक्रिता का नोबेल भी मिलेगा। आगेर पर लास्कर पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक को ही नोबेल दिया जाएगा है। ये तीन समानित वैज्ञानिक हैं—जोल डेवर, रेवेलाना मोजेश्वर और लोते बैंकर नुइसन।

इन्हें दिल्ली, 15 दिसंबर। सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों के कारण भारत के बैंकिंग सिस्टम में बड़ा सुधार देखने को मिला है और बैंकों 6 वर्षों से अधिक समय में शेड्यूल कर्मशियल बैंकों के ग्रांस एनपीए में 8.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के शेड्यूल कर्मशियल बैंकों का ग्रांस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) जून 2024 तक कम होकर 2.67 प्रतिशत रह गया है, जो कि मार्च 2018 तक 11.18 प्रतिशत था।

मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एस्प पर की गई एक पोर्टल में लिखा गया कि एसेट्स ब्यालाइट में कानूनी सुधार आया है और इस कारण प्रतिवर्ष दायां परफॉर्मेंट और मुझेह का इलाज की तलाश में मोटापे की दवाएं हाय लगी हैं। गौर करने की बात है कि मोटापे के मोर्चे पर वैज्ञानिक लंगे समय से काम कर रहे हैं। शल्य क्रिया के अलावा कुछ दवाएं भी उपलब्ध हैं, जो मोटापे को घोने में मदद कर सकती हैं। मोटापे के खिलाफ़ कामयाबी से यह पाता रहा है कि जीएलपी-1 आधारित दवाएं सिर्फ़ मोटापे और मुझेह का इलाज नहीं करती हैं। वे हृदय रोग, किंडली रोग जैसे भी उपलब्ध हो सकती हैं। इन दवाओं का इन्सेप्टल स्ट्रॉग्यू एप्लियाश में भी हो सकता है। इधर, रसीव एप्लियाश के मामले बढ़ रहे हैं, मतलब, सोते समय सांस रुक-रुकर करने की शिकायत बढ़ रही है। वास्तव में, एक अच्छी दवा जब बनती है, तो उसका व्यापक प्रयोग या उपयोग सामने आता है। जीएलपी-1 आधारित दवाओं पर और काम करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा सुरक्षित दवाएं लोगों तक पहुंच पाए।

वास्तव में, मोटापे पर दुनिया के अनेक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और तरह-तरह के शेष सामने आ रहे हैं। एक जान शोर से यह पाता रहता है कि मोटापा भूख से जुड़े न्यूरॉन्स के आसापास अणिक जाल के निर्माण से प्रेरित होता है। यह भी पाता रहा है कि प्रोटीन और शक्ति के एक नेटवर्क का सब्क्यू, जिसे बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स कहा जाता है, इन्सुलिन को भूख नियंत्रित करने वाले यूरो-स्ट्रक्चर पहुंचने से रोकता है, इससे मोटापे को बन मिलता है। मोटापे से जुड़ी एक खार यह भी है कि दुनिया भर में लोगों वायरस वजन कम करने के लिए वेगों जैसी शक्तिशाली दवाएं ले रहे हैं, पर क्या वर्त्यों को भी ऐसा करना चाहिए? दरअसल, वर्चों में बदला भोजन की लागत होती है, पर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये बच्चे जब बढ़ रहे हैं, तब उनके साथ व्यापा। कहीं ऐसा न हो कि वर्चों को बढ़ होने के बाद भारी नुकसान उठाना पड़े। आज मोटापे की दवा अपनी जगह एक बड़ी जरूरत बन गई है, लेकिन ज्यादातर विकित्सक यहीं चाहते हैं कि बच्चे हों या बढ़े, खायावानिक या प्राकृतिक प्रयोगों से ही अपना मोटापा घटाएं, इसी में स्थायी हित है।

भारत में प्रति व्यक्ति फलों और सब्जियों की उपलब्धता में वृद्धि



नई दिल्ली, 14 दिसंबर। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में भारत में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में क्रमशः 7 किलोग्राम और 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है।

फलों और सब्जियों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में मुख्य वृद्धि मय व्येस्ट, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 227 किलोग्राम रिकमेंडेशन प्रति व्यक्ति सलाना कम से कम 146 किलोग्राम है।

हालांकि, फलों के खरांव होने की व्यक्ति के दौरान व्यापार और रिकमेंडेशन प्रति वर्ष 2014-2024 में शहरीकरण में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में लगभग 115 आश्रम और जागरण की वृद्धि हुई है, उसके बाद राजस्थान में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

भारत की कुल अबादी का लागाम एक तिकोना के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि ज्यादातर उत्पादन पर जलवाया का प्रभाव नकारात्मक है।

पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन और मौसम की स्थिति के बीच अनुसारी संबंध है। आगेरी कृषि अनुसारी कामों की मात्रा में फल नहीं हो जाती है।

इन गर्मी और ठंड की लहरों का खायान उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसकी अधिकांश राज्यों में खायान उत्पादन और मौसम की स्थिति के बीच अनुसारी संबंध है। आगेरी कृषि अनुसारी कामों की मात्रा में फल नहीं हो जाती है।

हालांकि, फलों के खरांव होने की व्यक्ति के दौरान व्यापार और रिकमेंडेशन प्रति वर्ष 2014-2024 में शहरीकरण में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह' पर क्रांति डेटा को देखें, तो यह बताता है कि भारत प्रदेश में 97 वीपीएस की वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण डेटा पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण का सकैत देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्यादि हम 'व्यक्तिगत ग्राह

